



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042023-244917  
CG-DL-E-03042023-244917

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 1, 2023/चैत्र 11, 1945

No. 76]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1, 2023/CHAITRA 11, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(विदेश व्यापार महानिदेशालय )

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2023

सं. 2 / 2023

**विषय:** अग्रिम और ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारकों द्वारा निर्यात दायित्व में चूक के एककालिक समाधान हेतु एमनेस्टी स्कीम के संबंध में।

**फा. सं. 18 / 15 / एम-23 / पी-5.—समय—समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा (क) अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम और (ख) ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व में चूक के मामलों को बंद करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।**

## I) कवरेज़:

- i. विदेश व्यापार नीति, 2009-14 से 31.03.2015 तक के तहत जारी अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम (सभी प्रकार के) और ईपीसीजी स्कीम (सभी प्रकार के) के तहत जारी प्राधिकार पत्र, स्कीम के अंतर्गत आते हैं।

ii. विदेश व्यापार नीति, 2004–2009 और इससे पहले जारी अग्रिम प्राधिकार स्कीम (सभी प्रकार के) और ईपीसीजी स्कीम (सभी प्रकार के) के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के लिए कवरेज उन प्राधिकार पत्रों तक सीमित है, जिनकी निर्यात दायित्व अवधि (मूल या विस्तारित) 12.08.2013 के आगे वैध थी।

## II) स्कीम

- i. इस स्कीम को "अग्रिम और ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारकों द्वारा निर्यात दायित्व में चूक के एककालिक समाधान हेतु एमनेस्टी स्कीम" कहा जाएगा।
- ii. उपरोक्त पैरा (I) में उल्लिखित प्राधिकार पत्रों के निर्यात दायित्व (ईओ) को पूरा करने में चूक के सभी लंबित मामलों को प्राधिकार पत्र धारक द्वारा उन सभी सीमाशुल्कों जिन्हें अपूर्ण निर्यात दायित्व के अनुपात में छूट दी गई थी और इस तरह के ऐसे छूट प्राप्त शुल्कों के 100 प्रतिशत दर से ब्याज के भुगतान पर विनियमित किया जा सकता है। तथापि अतिरिक्त सीमाशुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क के हिस्से पर कोई ब्याज देय नहीं है।
- iii. वे सभी प्राधिकार पत्र धारक जो स्कीम का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, वे सभी संबंधित विवरण भरकर इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए अलग आवेदन प्रपत्र में वेबसाइट <https://www.dgft.gov.in> पर स्वयं को पंजीकृत करेंगे।
- iv. तत्पश्चात यदि संपूर्ण प्राधिकार पत्र चूक के अधीन है, तो आवेदक क्षेत्राधिकार प्राप्त संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास सीमाशुल्क और ब्याज का भुगतान कर सकते हैं और डीजीएफटी के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को इसका प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं।
- v. यदि आंशिक चूक है तो, आवेदक के विशिष्ट अनुरोध के आधार पर और आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत आवेदन के आधार पर डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारी, आवेदक को चूक का विवरण, जिस पर सीमाशुल्क और ब्याज देय है, सूचित करेगा।
- vi. तत्पश्चात आवेदक क्षेत्राधिकार प्राप्त संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास सीमाशुल्क और ब्याज का भुगतान कर सकता है और डीजीएफटी के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को इसका प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है।
- vii. यह लाभ उठाने का विकल्प चुनने वाले किसी भी प्राधिकार पत्र धारक को 30.06.2023 को या उससे पहले उपरोक्त पैरा (iii) में यथा उल्लिखित पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा और क्षेत्राधिकार प्राप्त संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास 30.09.2023 तक सीमाशुल्क और ब्याज का भुगतान करना होगा।
- viii. इस प्रकार के भुगतान के प्रमाण और प्रक्रिया पुस्तक के तहत यथा निर्धारित अन्य संबंधित दस्तावेजों के आधार पर, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी अनुरोध की जांच कर सकता है और निर्यात अथवा निर्वहन प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला एक पत्र जारी करेगा।
- ix. यहां तक कि जिन मामलों में मूल रूप से या अपील में न्यायनिर्णयन (अथवा लंबित न्याय निर्णयन) हो चुका है, उन्हें भी इस सार्वजनिक सूचना के तहत विनियमित किया जा सकता है। ऐसे मामलों के नियमितीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:
  - क. उन मामलों के संबंध में जिनका पहले ही न्यायनिर्णयन हो चुका है (या लंबित न्याय निर्णयन) और जहां अपील दायर नहीं की गई है, फर्म संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से क्लोजर पत्र की प्रति अधिनिर्णयन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।
  - ख. यदि कोई अपील दायर की गई है तो यह क्लोजर लेटर अपीलीय प्राधिकारी को जमा करना होगा। इस तरह के क्लोजर लेटर प्रस्तुत करने पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी, ऐसे मामले/अपील को बंद करने का निर्णय करेगा और इसकी सूचना अपीलकर्ता और संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को देगा।
- x. ऐसे मामलों, जिनकी जांच चल रही है, या जिसमें धोखाधड़ी, मिथ्या घोषणा या सामग्री और अथवा/पूँजीगत माल के अनधिकृत डाइवर्जन के संबंध में अधिनिर्णयन होना है, तो ये कवरेज से बाहर होंगे।
- xi. कानून के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी राशि की न तो सेनेवेट क्रेडिट, न ही क्रेडिट की वापसी, इस स्कीम के अंतर्गत भुगतान किए शुल्क पर अनुमत की जाएगी। आवेदक को यह वचनबद्धता भी देनी होगी कि

सेनवेट क्रेडिट या इस स्कीम के तहत भुगतान की गई किसी भी शुल्क की वापसी के लिए किसी भी प्राधिकारी के समक्ष और /या न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन दायर नहीं करेंगे।

- xii. यदि लागू ब्याज सहित शुल्क पहले ही पूर्ण रूप से जमा कर दिया गया है, तो मामला कवरेज के लिए पात्र नहीं होगा।
- xiii. संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट भरने की प्रणाली सहित आवश्यक प्रक्रियाएं अलग से दर्शायी जाएंगी।

**[उदाहरण 1: जहाँ संपूर्ण निर्यात दायित्व पूरा नहीं किया जा सका]:** यदि निर्यात दायित्व में चूक 100 प्रतिशत है तो, इसका अर्थ होगा कि बचाई गई शुल्क की पूरी रकम वापस करनी होगी। इस बचाई गई शुल्क राशि पर ब्याज की गणना आयात की तारीख से भुगतान की तारीख तक की जानी है। अप्रयुक्त छूट प्राप्त सामग्री का कुल सीआईएफ मूल्य मानो 100/- रुपए हैं, सभी छूट प्राप्त सीमाशुल्क (अतिरिक्त सीमाशुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क सहित) मानो 50/- रुपए हैं। सीमाशुल्क छूट (अतिरिक्त सीमाशुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क को छोड़कर) वाला हिस्सा 32 रुपये है तो अधिकतम देय ब्याज 32 रुपये (32 रुपये का 100 प्रतिशत) है। इसलिए इस मामले को विनियमित करने हेतु प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा अधिकतम देय राशि  $50 + 32 = 82$  रुपये होगी।

**उदाहरण 2: जहाँ निर्यात दायित्व पूर्ति में कमी है:** प्राधिकार पत्र के कुल सीआईएफ मूल्य में 500 रुपये है, निर्यात दायित्व में चूक 40 प्रतिशत थी, तब बचाई गई शुल्क राशि की तदनुरूपी सीआईएफ मूल्य 200 रुपये (500 रुपये का 40 प्रतिशत) हो जाता है। सभी सीमाशुल्क छूट (अतिरिक्त सीमाशुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क सहित) 100 रुपये हैं। सीमाशुल्क छूट (अतिरिक्त सीमाशुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क को छोड़कर) हिस्सा 64 रुपये है तो देय अधिकतम ब्याज 64/- रु. से होगा (64 रुपये का 100 प्रतिशत)। इसलिए इस मामले को विनियमित करने हेतु प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा अधिकतम देय राशि  $100 + 64 = 164$  रुपये होगी।

**इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** अग्रिम और ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारकों द्वारा निर्यात दायित्व में चूक के एककालिक समाधान हेतु एमनेस्टी स्कीम के तहत अग्रिम प्राधिकार-पत्र और ईपीसीजी प्राधिकार-पत्रों के निर्यात दायित्व चूक के मामलों में ईओडीसी प्रदान करने / विनियमित करने हेतु एक कालिक सुविधा प्रदान की जा रही है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### (Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st April, 2023

No. 2/2023

**Subject: Amnesty scheme for one time settlement of default in export obligation by Advance and EPCG authorization holders -reg.**

**F. No. 18/15/AM-23/P-5.—**In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in procedure to close cases of default in Export Obligation under (a) Advance Authorisation Scheme and (b) EPCG Scheme.

**I) Coverage:**

- i. The Authorisations issued under Advance Authorisation Scheme (all variants) and EPCG Scheme (all variants) issued under Foreign Trade Policy, 2009-14 till 31.03.2015 are covered under the Scheme.

- ii. For Authorizations issued under Advance Authorisation Scheme (all variants) and EPCG Scheme (all variants) issued under Foreign Trade Policy, 2004-2009 and before, the coverage is limited to those authorizations whose Export Obligation Period (original or extended) was valid beyond 12.08.2013.

## II) The scheme

- i. This scheme is called “Amnesty scheme for one time settlement of default in export obligation by Advance and EPCG authorization holders”
- ii. All pending cases of the default in meeting Export Obligation (EO) of authorizations mentioned in para (I) above can be regularised by the authorisation holder on payment of all customs duties that were exempted in proportion to unfulfilled Export Obligation and interest at the rate of 100% of such duties exempted. However, no interest is payable on the portion of Additional Customs Duty and Special Additional Customs Duty.
- iii. All those authorization holders who are interested to avail the Scheme shall register themselves in website: <https://www.dgft.gov.in> in a separate application form provided for this purpose by filling all relevant details.
- iv. Thereafter, if entire authorization is under default, the applicants can pay Customs duty plus interest with the Jurisdictional Customs authorities concerned and submit proof thereof to the Regional Authority of DGFT concerned.
- v. If there is partial default, the Regional Authority of DGFT on the basis of specific request of the applicant and on the basis of application filed for Export Obligation Discharge Certificate along with the necessary supporting documents, shall intimate to the applicant the details of default on which Customs duty and interest is payable.
- vi. The applicant thereafter can pay Customs duty plus interest with the Jurisdictional Customs authorities concerned and submit proof thereof to the regional authority of DGFT concerned.
- vii. Any authorisation holder choosing to avail this benefit must complete the process of registration as mentioned in para (iii) above on or before 30.06.2023 and payment of Customs duty plus interest with the Jurisdictional Customs Authorities concerned shall be completed by 30.09.2023.
- viii. Based on the evidence of such payment and other relevant documents as prescribed under the Handbook of Procedures, concerned RA may examine the request and issue a letter granting Export Obligation Discharge Certificate (EODC).
- ix. Even cases which have already been adjudicated (or pending adjudication), either originally or in appeal, can also be regularized under this Public Notice. The procedure for regularization of such cases would be as under :-

  - a. In respect of cases which have already been adjudicated (or pending adjudication) and where appeal has not been filed, firms will produce a copy of this closure letter from the concerned RA, to the Adjudicating Authority.
  - b. In case an appeal has been filed, then this closure letter will have to be submitted to the Appellate Authority. On submission of such closure letter Adjudicating Authority/Appellate Authority will decide on closure of such case/appeal and will inform the same to the Appellant and to the concerned RA.

- x. Cases under investigation or cases adjudicated for/involving fraud, misdeclaration or unauthorised diversion of material and/or capital goods will be excluded from the coverage.
- xi. Neither CENVAT Credit nor Refund, under any provision of law, of any amount shall be allowed on duties paid under this scheme. The applicant shall also give an undertaking that they will not file any application for CENVAT Credit or refund of any duty paid under this scheme before any authority and/or before any court of law.
- xii. If duty along with applicable interest has already been deposited in full, the case would not be eligible for coverage.
- xiii. Necessary procedures including a system of filing required reports by the respective RAs would be indicated separately.

**Example 1: Where entire EO could not be fulfilled:** - If the default in EO is 100%, this would mean the complete duty saved amount has to be refunded. The interest on this duty saved amount has to be calculated from the date of import till the date of payment. In the total CIF value of unutilised exempted material is say Rs. 100/-, all the customs duties (including Additional Customs Duty and Special Additional Customs Duty) exempted is say Rs.50/- . The Customs duties exempted (except Additional Customs Duty and Special

Additional Customs Duty) portion is say Rs.32/- then interest payable is maximum of Rs. 32/- (100% of Rs.32/-). Therefore for regularising this case the maximum amount payable by the authorisation holder would be Rs. 50+32/- =Rs.82/-.

**Example 2: Where there is a shortfall in EO fulfillment:-** In the total CIF value of authorization is say Rs. 500/-, the default in EO were 40%, then the corresponding CIF value of duty saved amount becomes Rs. 200 (40% of Rs. 500). All the customs duties exempted (including Additional Customs Duty and Special Additional Customs Duty) is say Rs.100/- . The Customs duties exempted (except Additional Customs Duty and Special Additional Customs Duty) portion is say Rs.64/- then maximum interest payable is Rs.64/- (100% of Rs.64/-). Therefore for regularising this case the maximum amount payable by the authorisation holder would be Rs. 100+64/- =Rs.164/-]

**Effect of this Public Notice:** One time facility is being provided for grant of EODC/ regularisation of cases of EO default of Advance Authorisation and EPCG authorizations under “Amnesty scheme for one time settlement of default in export obligation by Advance and EPCG authorization holders”

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.